



2026:AHC:127617

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19281 सन् 2026

अमन हुसैन उर्फ अमन्ना

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिता सिंह, कुमारी पूनम राजपूत, निर्मला कुमारी,
प्रेम बाबू वर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. दिनांक 5.6.2026 की पुलिस आख्या के आधार पर वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र की लंबितता के संबंध में शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या 2 को तामील की जा चुकी है। सूचना तामील किए जाने के बावजूद, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र का प्रतिवाद करने हेतु विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की मुकदमा अपराध संख्या 784/2025, धारा 76, 115(2), 333, 351(2) बी.एन.एस. तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत, थाना रामगढ़, जनपद फिरोजाबाद में, जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कथन किया गया है कि अभिकथित घटना दिनांक 7.12.2025 को घटित हुई थी, जबकि प्राथमिकी दिनांक 10.12.2025 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब का अभियोजन पक्ष द्वारा उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के शरीर पर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई चोट नहीं है। आवेदक के 20 मामलों के आपराधिक इतिहास को जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर संख्या 17 तथा अनुपूरक शपथ पत्र के प्रस्तर 3 और 4 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि आवेदक दिनांक 8.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा यह कथन किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

6. मैंने पक्षों की प्रतिस्पर्धी दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी दलीलों, अभिकथनों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, आपराधिक इतिहास के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदक-अमन हुसैन उर्फ अमन्ना को व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि की दो प्रतिभूतियों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह किसी स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के अभाव में उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 बी.एन.एस. के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप-विरचन, तथा (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

10. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।